

प्रेषक,

एनोएसोनपलच्चाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: २। जनवरी, 2008

विषय:- श्रीमती तारावती मैमोरियल एजूकेशन सोसायटी, रुड़की को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम सालियर साल्हापुर मु० में कुल ०.८१६८ हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 721/भूमि व्यवस्था-भूक्य दिनांक 13-12-2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती तारावती मैमोरियल एजूकेशन सोसायटी, रुड़की को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154 (4) (३)(ब)(III) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम सालियर साल्हापुर मु० परगना भगवानपुर में कुल ०.८१६८ हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलौदटर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्याय उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

7— स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8— भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा जिसमें उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि या सार्वजनिक भूमि के उपयोग की संभावना न हो।

9— भूमि का अंतरण/विक्याय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसे विक्याय के लिये सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत र्खीकृति निररत कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्चाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

.....(3)

